

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 207  
उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

207. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और आरयूएसए के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है और इस योजना के तहत आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके आरंभ के बाद से उद्देश्यों को हासिल किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों की उन्नयन योजना पर कोई उच्च शिक्षा योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नए विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के निधियन हेतु समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में संचालित एक व्यापक योजना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हुए मौजूदा राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना कि वे निर्धारित मानकों और मानदंडों का अनुपालन करें और एक अनिवार्य गुणवत्ता

आश्वासन फ्रेमवर्क के रूप में प्रत्यायन को अपनाना; ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापरक संस्थाओं तक पहुंच को सुगम बनाकर क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना; सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना; समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनु.जा./अनु.ज.जा./ ओबीसी और दिव्यांगजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना है। अभिशासन, अकादमिक, संबद्धता और प्रत्यायन सुधारों जैसे परिवर्तनकारी सुधार राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की पूर्व-अपेक्षाएं हैं। रूसा के अंतर्गत सभी प्रकार का निधियन मानक आधारित है और भावी अनुदान प्रदर्शन और परिणाम पर निर्भर हैं।

रूसा योजना, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और समानता को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक रही है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समग्र सकल नामांकन अनुपात 2012-13 में 21.5 से 2018-19 में अर्थात् रूसा की शुरुआत के समय से बढ़कर 26.3 हो गया। छात्राओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के नामांकन में भी काफी सुधार हुआ है। रूसा में संबद्धता सुधारों के जरिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों की संख्या के संबंध में राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों का आकार सही करने का अधिदेश है। तदनुसार राज्यों ने अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों को दो भागों/तीन भागों में विभाजित कर दिया है। अभी तक, लक्षद्वीप के अलावा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रूसा में भाग ले रहे हैं।

इस योजना का ब्यौरा [rusa.nic.in](http://rusa.nic.in) पर उपलब्ध है। रूसा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग) : इस योजना के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को जारी निधियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल योग
कुल जारी	7.4479	86.42	100.1	14.1	208.06

(घ): रूसा के तहत, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और संपूर्ण अवसंरचना में सुधार करने के लिए, विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान घटक के तहत 9 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार घटक के तहत 1 विश्वविद्यालय को केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त, चयनित विश्वविद्यालयों में वृहत गुणवत्ता और उत्कृष्टता घटक के तहत 2 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता भी अनुमोदित की गई है।

(ड.) : रूसा के तहत, विश्वविद्यालयों का सृजन, स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन या कॉलेजों के क्लस्टर में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य को योग्य प्रस्ताव न मिलने के कारण ऐसी कोई यूनिट अनुमोदित नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*

**संलग्नक**

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संबंध में माननीय सदस्य श्री केसिनेनी श्रीनिवास और श्री बी.एन. बचेगौडा द्वारा दिनांक 18.11.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 207 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

**रूसा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का विवरण**

क्र.सं.	राज्य	जारी निधि (रू. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	274.42
2	अरुणाचल प्रदेश	72.39
3	अंडमान और निकोबार द्वीप	13.36
4	असम	402.83
5	बिहार	123.45
6	छत्तीसगढ़	179.56
7	चंडीगढ़	29.77
8	दिल्ली	1.52
9	दादर और नगर हवेली	4.78
10	दमन और दीव	3.94
11	गुजरात	167.90
12	गोवा	47.27
13	हरियाणा	148.96
14	हिमाचल प्रदेश	183.68
15	जम्मू और कश्मीर	293.39
16	झारखंड	178.08
17	कर्नाटक	341.61
18	केरल	183.87
19	मणिपुर	100.48
20	मध्य प्रदेश	225.66
21	महाराष्ट्र	198.91
22	मेघालय	70.23
23	मिजोरम	101.67
24	नगालैंड	82.66
25	ओडिशा	390.38
26	पंजाब	163.12
27	पुडुचेरी	52.80
28	राजस्थान	261.27
29	तमिलनाडु	293.56
30	तेलंगाना	149.08
31	त्रिपुरा	44.05
32	सिक्किम	72.69
33	उत्तर प्रदेश	473.07
34	उत्तराखंड	166.55
35	पश्चिम बंगाल	332.10

	कुल	5829.04
--	-----	---------

\*\*\*\*\*